प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
02.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए कर हस्तांतरण में 13 हजार 9 सौ 49 करोड़ रुपये का प्रावधान–अनुदान सहायता के तहत हिमाचल को मिलेंगे 10 हजार 2 सौ 43 करोड़।
- केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा–हिमाचल में रेल विस्तार के लिए दो हजार 9 सौ 11 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने फायर एनओसी के कारण होम स्टे के पंजीकरण का रेन्यूल न रोकने के दिए निर्देश।
- लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा– दलगत राजनीति से हटकर केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए राजस्व घाटा अनुदान का मुद्दा।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने के बजाए राज्य की वित्तीय स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी।

अब समाचार विस्तार से.....

केंद्रीय हस्तांतरण

केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026– 27 में हिमाचल के लिए कर हस्तांतरण में 13 हजार 9 सौ 49 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। इसी तरह अनुदान सहायता में प्रदेश के लिए वर्ष 2025–26 में 10 हजार 2 सौ 43 करोड़ रुपये के बजट आबंटन का प्रावधान किया गया है। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के तहत हिमाचल को 2020–21 से 2025–26 तक 8 हजार 3 सौ 9 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता दी जाती है और ब्याज केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा भारत माला परियोजना के पहले चरण के तहत हिमाचल में 9 हजार 9 सौ 64 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत से एक सौ 67 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के विकास को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मंडी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए साईट क्लीयरेंस प्रदान कर दी है।

अश्वनी वैष्णव

केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को रेल विस्तार के लिए दो हजार 9 सौ 11 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ये राशि पूर्व में केंद्र में रही कांग्रेस सरकारों द्वारा दी गई राशि से 27 गुणा अधिक है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 17 हजार 7 सौ 11 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं।

अमृत स्टेशन योजना का जिक्र करते हुए अश्वनी वैष्णव ने बताया कि हिमाचल के चार स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, जिन पर 46 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैजनाथ– पपरोला, अम्ब –अंदौरा रेलवे स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से रेल नेटवर्क के विस्तार में पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाने में रेल मंत्रालय का सहयोग करने का आग्रह किया है।

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार होम–स्टे संचालकों और होटल मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज शिमला में होम–स्टे पोर्टल के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ही होम–स्टे का पंजीकरण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र के कारण होम–स्टे के पंजीकरण के रिन्यूअल को न रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को ऐसे होटलों को प्रोविजनल पंजीकरण प्रदान करने को कहा, ताकि उनका व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित होता रहे। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत होम–स्टे योजना आरम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत अधिकतम छह कमरे की सुविधा का होम–स्टे पंजीकृत किया जा सकता है।

विक्रमादित्य सिंह

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आजादी के बाद से ही राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा है, मगर बजट में उसे खत्म कर दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष रखने की बात कही है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई ड्रैनेज नीति लाई जाएगी ताकि सड़कों को नुकसान से बचाया जा सके।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने के बजाए मुख्यमंत्री को राज्य की वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय दी गई झूठी गारंटियों को पूरा करना केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को आधार बनाकर पूरे देश के लिए समान नीतियां बनाती है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार केंद्र प्रायोजित करीब एक सौ 91 योजनाओं में राज्य की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी देने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में मनरेगा के करीब एक लाख 71 हजार कार्य लंबित है और 6 सौ 55 लोगों को एक दिन का भी काम नहीं मिल पाया है।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आरडीजी को लेकर कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा आरडीजी को बंद किए जाने के संबंध की गई टिप्पणीयों पर विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से साझा की है, जिसमें प्रदेश के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की भरपूर मदद कर रही है जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार से संभल नहीं रही है।

''अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए कर हस्तांतरण में 13 हजार 9 सौ 49 करोड़ रुपये का प्रावधान–अनुदान सहायता के तहत हिमाचल को मिलेंगे 10 हजार 2 सौ 43 करोड़।
- केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा–हिमाचल में रेल विस्तार के लिए दो हजार 9 सौ 11 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने फायर एनओसी के कारण होम स्टे के पंजीकरण का रेन्यूल न रोकने के दिए निर्देश।
- लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा– दलगत राजनीति से हटकर केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए राजस्व घाटा अनुदान का मुद्दा।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने के बजाए राज्य की वित्तीय स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी।

———————————